जगदेव कृष्ण नंदा और अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

11 अगस्त, 1989

समतुल्य उद्धरण: (1990) 97 पीएलआर 97

लेखक: एम अग्निहोत्री

बेंच: एम अग्निहोत्री

निर्णय

न्यायमूर्ति एमआर अग्निहोत्री

1. यह निर्णय सिविल रिट याचिका संख्या 1867,19,90 का निपटान करेगा; 2210 2655,::3885, 4665, 4747,4748, 4836 और 1989 के 65एल7 इन सभी मामलों में तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं। संदर्भ के लिए 1980 के सीडब्ल्यूपी नंबर 1990 से तथ्यात्मक स्थिति मांगी गई है।

2 भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों और सेवा शर्तों की प्रचलित संरचना की जांच करने के उद्देश्य से वर्ष 1983 में एक वेतन आयोग की स्थापना की, जिसे लोकप्रिय रूप से "चौथे वेतन आयोग" के रूप में जाना जाता है; साथ ही अतीत और भविष्य दोनों के पेंशनभोगियों के लिए एक उचित पेंशन संरचना बनाने की दृष्टि से जांच करना। इस वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी और आयोग की सिफारिशों को भारत सरकार के सेवारत कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों यानी पुराने और नए, जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, के संबंध में विधिवत लागू किया गया। हरियाणा राज्य के पेंशनभोगियों के संबंध में, राज्य सरकार ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने और लागू करने का निर्णय लिया और उस निर्णय के अनुसरण में। राज्य सरकार ने दिनांक 29 4-1987 को एक अधिसूचना जारी करके अपने कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित किया। इस अधिसूचना के आधार पर, वेतनमान को 1-1,-19867 से संशोधित किया गया। वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप, 1 जनवरी 1986 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी बढ़ी हुई दर पर वेतन और पेंशन के लाभ के हकदार बन गए। उस हद तक कर्मचारियों की शिकायत का समाधान किया गया।

3. हालाँकि, मौजूदा पेंशन, मौजूदा महंगाई राहत और अपने स्वयं के कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से प्राप्त अतिरिक्त लाभों को एक साथ जोड़ने के बाद पेंशन को समेकित करके पेंशन संरचना का युक्तिकरण, जैसा कि उनके नीति पत्र में निहित है। दिनांक 16 अप्रैल, 1987 (अनुलग्नक पी. एल) को हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के मामले में लागू किया जाना बाकी है। तदनुसार, 3 नवंबर, 1988 को; की सिफारिशों पर हरियाणा राज्य ने भी हरियाणा राज्य के कर्मचारियों के मामले में पेंशन लाभ के उदारीकरण के संबंध में आदेश जारी किए। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए चौथे वेतन आयोग के अनुसार, हरियाणा के जो कर्मचारी 31 मार्च, 1985 से

सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें केंद्र सरकार की तर्ज पर पेंशन दी गई, जबकि उन कर्मचारियों को पेंशन के लिए ऐसा कोई लाभ नहीं दिया गया, जो पहले सेवानिवृत्त हुए थे। 31 मार्च, 1985. 3 नवंबर, 1988 को राज्य सरकार द्वारा जारी नीति पत्र, जो इन रिट याचिकाओं में विचार का विषय है, अनुलग्नक पी 2 के रूप में संलग्न है। इसके अलावा, हालांकि पेंशन लाभ के बढ़ते संशोधन और उदारीकरण के परिणामस्वरूप वेतन का बकाया है , पेंशन, मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी आदि कर्मचारियों को देने का आदेश दिया गया था, फिर भी 3 नवंबर, 1988 के पत्र के अंत में निम्नलिखित प्रभाव के लिए एक राइडर जोड़ा गया था: -

"30-6-1988 तक आदेश के क्रियान्वयन के आधार पर देय होने वाले सभी प्रकार के बकाया का भुगतान राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय बचत योजनाओं में दीर्घकालिक जमा के रूप में किया जा सकता है।"

यह उत्तरदाताओं की इस कार्रवाई के खिलाफ है कि याचिकाकर्ता जो हैं; हरियाणा राज्य के पेंशनभोगी व्यथित महसूस कर रहे हैं और उन्होंने निम्नलिखित राहत देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है:--

4 सबसे पहले, सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उन सभी को पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए, चाहे वे 31-3-1985 से पहले या बाद में सेवानिवृत्त हों, एक समान और एक समान तरीके से होना चाहिए, बिना किसी आधार पर भेदभाव के। सेवानिवृत्ति की अलग-अलग तारीखें। दूसरे शब्दों में, "चौथे वेतन; आयोग" की रिपोर्ट का लाभ, जिसे हरियाणा राज्य द्वारा पहले ही स्वीकार और लागू किया जा चुका है, 31-3-1985 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को उसी तरह से दिया जाना चाहिए। जैसा कि 31-3-1985 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के मामले में किया गया है, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, तारीख के आधार पर कोई भी कृत्रिम वर्गीकरण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। उनके तर्क के समर्थन में, डीएस नाकारा और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए डीएस नाकारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध प्राधिकारी पर मजबूत निर्भरता रखी गई है। बनाम भारत संघ , एआईआर 1983 एससी 130; जिसमें लगभग ऐसी ही स्थिति में, सेवानिवृत्ति की तारीखों के आधार पर कृत्रिम वर्गीकरण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।

5. दूसरी राहत की मांग 3 नवंबर, 1988 के पत्र (अनुलग्नक पी 2) में जोड़े गए राइडर को रद्द करने की है, जिसके द्वारा कार्यान्वयन के आधार पर देय बकाया को दीर्घकालिक जमा के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया है। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और राष्ट्रीय बचत योजनाएँ, आदि यानी नकद में नहीं और तुरंत एकमुश्त राशि में।

6. रिट याचिका के जवाब में, हरियाणा राज्य और महालेखाकार, हरियाणा द्वारा अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए हैं। महालेखाकार, हरियाणा का रुख सरल है यानी 31.3 से प्रभावी पेंशन के संशोधन के आदेश। हरियाणा सरकार के पेंशनभोगियों के संबंध में 1985 के नियम अभी भी राज्य सरकार से प्रतीक्षित हैं और उन्हें केवल समय-समय पर राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करना है। जहां तक हरियाणा राज्य का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा दलील दी गई है कि '31.3.1985 से पहले सेवानिवृत्त हुए इन पेंशनभोगियों को अतिरिक्त राहत देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। "दूसरे तर्क के संबंध में, उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया रुख यह है कि एनएससी/एनएसएस के रूप में बकाया भुगतान के लिए सरकार के आदेश राज्य की तंग वित्तीय स्थिति और राज्य की ईमानदारी को देखते हुए पारित

किए गए थे। सरकार अपने पेंशनभोगियों को अतिरिक्त राहत देगी। इससे इनकार किया जाता है कि राज्य सरकार की यह कार्रवाई मनमानी और अन्यायपूर्ण है।"

7. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और उनकी दलीलों की जांच करने के बाद, मेरा मानना है कि प्रतिवादी राज्य हरियाणा द्वारा लिया गया रुख कानून की दृष्टि से पूरी तरह से अस्थिर है। भारत सरकार द्वारा चौथे वेतन आयोग की स्थापना का उद्देश्य मौजूदा मुद्रास्फीति को देखते हुए कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करना था। वास्तव में एकमात्र तार्किक आधार पैसे की क्रय शक्ति में गिरावट की भरपाई करना और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी स्थिति आदि के अनुरूप सम्मानजनक जीवन स्तर बनाए रखने में मदद करना होना चाहिए। जाहिर है, इरादा उन कर्मचारियों को बाहर करने का नहीं था जो वेतन आयोग की स्थापना से पहले या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों। इसके अलावा, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले कृत्रिम वर्गीकरण के बीच कोई उचित संबंध नहीं है। वास्तव में, ऐसी ही स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्ति की तारीखों के आधार पर भारत सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले घृणित भेदभाव को खत्म कर दिया। हरियाणा राज्य द्वारा अपनाए गए रुख का खोखलापन उत्तर के पैरा 7 में की गई आधी-अधूरी दलील से भी स्पष्ट है कि मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन था, यहां तक कि उस समय हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता भी थे। मामलों की सुनवाई करते हुए कहा गया कि भेदभाव को चार महीने की अवधि के भीतर दूर कर दिया जाएगा। चौथे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन में पहले ही हो चुकी देरी और उन अनिवार्य कारणों को ध्यान में रखते हुए, जिनके लिए सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन लाभ देने के मामले में उनके बराबर मुआवजा दिया जाना है, किसी अवधि तक इंतजार करना आवश्यक नहीं है। मामले को एक बार फिर राज्य सरकार के विचाराधीन छोड़ कर चार महीने का समय दिया गया। हालाँकि, राज्य सरकार इस समय का उपयोग प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में विवरण तैयार करने और पेंशन की राशि और ग्रेच्युटी आदि जैसे अन्य सेवानिवृत्त लाभों को फिर से तय करने के लिए कर सकती है। ताकि इस वेतन निर्धारण के सभी लाभ वास्तव में याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराए जा सकें। , सकारात्मक रूप से चार महीने की अवधि के भीतर।

8. जहां तक उपरोक्त पत्र के सवार पर हमले का सवाल है, उसे मार गिराने में कोई कठिनाई नहीं है। हरियाणा राज्य के कर्मचारियों और उन लोगों की सेवा शर्तें जिन्हें 1.11.1966 से इसे आवंटित किया गया है, वैधानिक सेवा नियमों द्वारा शासित होती हैं। आरंभ करने के लिए, भारत सरकार अधिनियम, 1919 की धारा 96 बी के तहत संयुक्त पंजाब प्रांत के लिए सिविल सेवा विनियम तैयार किए गए थे। उन्हें भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 266 के तहत लागू रखा गया था, और लागू होने के बाद भी संविधान में उनके वैधानिक बल को जारी रखने के लिए अनुच्छेद 313 में एक विशिष्ट प्रावधान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह तय किया गया है कि पेंशन, ग्रेच्युटी, वेतन, मजदूरी आदि की प्रकृति के सेवा नियमों को अनुच्छेद 309 के तहत या भारत सरकार अधिनियम, 1935 या भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत संशोधित या संशोधित नहीं किया जा सकता है। मात्र कार्यकारी आदेशों द्वारा। वे कर्मचारियों की सेवा शर्तों का हिस्सा बनते हैं। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत बनाए गए पंजाब सिविल सेवा नियमों का यह आदेश है कि वेतन और मजदूरी का भुगतान नकद में किया जाना चाहिए। यह प्रावधान वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अनुसार "सभी मजदूरी का भुगतान चालू सिक्के या मुद्रा नोटों या दोनों में किया जाएगा"। यदि दीर्घकालिक जमा या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में भुगतान करने के लिए इस प्रावधान को संशोधित या हस्तक्षेप करना था, तो या तो राज्य विधानमंडल का एक अधिनियम अधिनियमित किया जाना चाहिए था या अनुच्छेद 309 के तहत एक वैधानिक नियम बनाया जाना चाहिए था । संविधान। केवल

कार्यकारी आदेश उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिसका प्रभाव वैधानिक सेवा नियमों में संशोधन करने पर पड़ता है।

9. वास्तव में ऐसी ही स्थिति 1962 में पंजाब राज्य में उत्पन्न हुई थी जब राज्य सरकार द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश करके एक निश्चित राशि से अधिक बोनस का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। कानून बनाने और वेतन भुगतान अधिनियम , 1936 को वेतन भुगतान (पंजाब संशोधन) अधिनियम , 1962 (1962 का पंजाब अधिनियम संख्या 15) द्वारा संशोधित किया गया था, संशोधन अधिनियम की धारा 2 के आधार पर , भुगतान की धारा 6 के आधार पर वेतन अधिनियम, 1936 को पंजाब राज्य में लागू करने के लिए संशोधित किया गया और निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की गई:-

"6. मजदूरी का भुगतान चालू सिक्के या मुद्रा नोटों में किया जाएगा। - एएच मजदूरी का भुगतान चालू सिक्के या मुद्रा नोटों या दोनों में किया जाएगा।

बशर्ते कि जहां किसी नियोजित व्यक्ति को देय बोनस की राशि उस वर्ष के लिए एक सौ रुपये की राशि से अधिक हो, जिससे बोनस संबंधित है, एक सौ रुपये से अधिक बोनस की राशि का पचास प्रतिशत भुगतान किया जाएगा या निवेश किया जाएगा। निर्धारित तरीके "

यह स्पष्ट है कि इस कानून के अभाव में उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका और क़ानून में प्रावधान किया गया। वेतन भुगतान अधिनियम को केवल कार्यकारी आदेशों द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक होगा कि पंजाब के संशोधन अधिनियम को भी इसके तुरंत बाद 1 अप्रैल, 1963 से पंजाब अधिनियम 2, 1954 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तर्क, चूंकि पंजाब सिविल सेवा नियम, जो प्रकृति में वैधानिक हैं और पेंशन और अन्य लाभों के नकद भुगतान का प्रावधान करते हैं, अनुबंध पी. 2 के रूप में एक कार्यकारी आदेश भुगतान के तरीके को संशोधित नहीं कर सकता है। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य , एआईआर 1967 एससी 1910, राजेंद्र नारायण सिंह और अन्य के मामलों में । बिहार राज्य , एआईआर 1980 एससी1246, एसएल सचदेव बनाम भारत संघ , एआईआर 1981 एससी411 और पीडी अग्रवाल बनाम वीपी राज्य एआईआर 1987 एससी 1676। यह माना गया है कि वैधानिक नियमों में निहित प्रावधानों को कार्यकारी आदेशों द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, दिनांक 3-11-1988 के पत्र के अंतिम पैरा में निहित शर्त प्रथमतः अवैध है।

10. परिणामस्वरूप, इन याचिकाओं को अनुमति दी जाती है और परमादेश की रिट जारी करके उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं और समान रूप से स्थित अन्य सभी कर्मचारियों को निम्नलिखित राहत देने का निर्देश दिया जाता है: -

(i) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के आधार पर पेंशन लाभ उन सभी सरकारी सेवकों पर भी समान रूप से लागू और उपलब्ध होंगे, जो 31.3.1985 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। और उसी दर के अनुसार ये लाभ उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध हैं; और

(ii) पत्र दिनांक 3.11.1981 में निहित निर्णय के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लाभ की गणना की जाएगी और याचिकाकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों को आज से चार महीने की अवधि के भीतर नकद में भुगतान किया जाएगा।

11. याचिकाकर्ता उन याचिकाओं की लागत के भी हकदार होंगे जो रुपये में निर्धारित हैं। प्रत्येक मामले में 500/- रु.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)